



हरियाणा सरकार



श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री



श्री मनोहर लाल
मुख्यमंत्री

हरियाणा
100 दिन
बेहतरीन

सुशासन से सुगम जीवन की ओर

सुशासन संकल्प वर्ष-2020



शिक्षा, स्वास्थ्य,
सुरक्षा एवं स्वावलम्बन

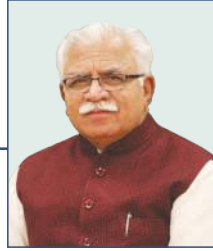
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

मेरी फसल - मेरा ब्यौरा

लाल डोरा मुक्त गांव

परिवार पहचान-पत्र

संदेश

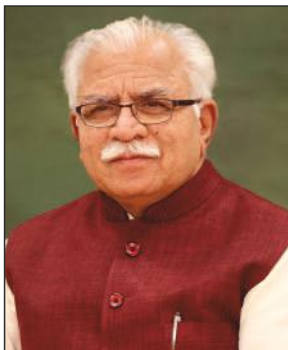


27 अक्टूबर, 2019 को हमने राज्य की जनता का विश्वास जीतते हुए एक नई सोच और संकल्पना के साथ पुनः प्रदेश की बागडोर संभाली। अपने कार्यकाल के पहले वर्ष को 'सुशासन संकल्प वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय हमारी इसी सोच को दर्शाता है कि राज्य सरकार पहले भी पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन देने के लिए कटिबद्ध रही है और आगे भी रहेगी।

प्रदेश की सरकार बनने के मात्र 100 दिनों के अल्प समय में ही सरकार ने नई ऑनलाइन सेवाएं जैसे लाल डोना मुक्त गांवों का डिजिटल मैप, लोकायुक्त पोर्टल, वेब हेल्थिनेस आदि शुरू की हैं, ताकि प्रदेश की जनता इनके माध्यम से सीधे तौर पर जुड़ सके। आज जन-कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सेवाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं, इस पारदर्शी प्रशासन ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी है और जन सेवाओं का सीधा लाभ सही लाभार्थी को प्राप्त हो रहा है। इसी कड़ी में समाज कल्याण के दायरे में आने वाली प्रमुख समस्याओं में भी बढ़ोतरी की गई है।

राज्य के विकास और समाज के उत्थान का यह क्रम ऐसे ही चलता रहेगा, बस जरूरत इस बात की है कि हम इस अपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर अपना-अपना योगदान दें। मैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सहयोग से हम हरियाणा को एक नई पहचान देंगे।

मनोहर लाल
मुख्यमंत्री, हरियाणा



**मनोहर लाल
मुख्यमंत्री**

कार्यालय :
(चौथी मंजिल, सचिवालय)

0172-2749396

0172-2749409

निवास :

1/3, चण्डीगढ़

0172-2749394



**दुष्यंत चौटाला
उप-मुख्यमंत्री**

कार्यालय :
(कमरा नं० 40/5, सचिवालय)

0172-2740212

निवास :

48/2, चण्डीगढ़

0172-2741280

मंत्री परिषद्

नाम एवं पद

दूरभाष

निवास पता



अनिल विज
गृह मंत्री

(कमरा नं० 32/8, सचिवालय)

0172-2740793 9416211001 —



कंवर पाल
शिक्षा मंत्री

(कमरा नं० 34/8, सचिवालय)

0172-2740010 2742544 4/3
चण्डीगढ़



मूल चंद
परिवहन मंत्री

(कमरा नं० 49/8, सचिवालय)

0172-2740157 2790777 75/7
चण्डीगढ़



रंजीत चौटाला
विद्युत मंत्री

(कमरा नं० 39/8, सचिवालय)

0172-2740231 2742032 32/3
चण्डीगढ़



जय प्रकाश दलाल
कृषि मंत्री

(कमरा नं० 42/6, सचिवालय)

0172-2743709 2540098 239/16
चण्डीगढ़



डॉ. बनवारी लाल
सहकारिता मंत्री

(कमरा नं० 24/8, सचिवालय)

0172-2740906 2741061 52/5
चण्डीगढ़

राज्य मंत्री

नाम एवं पद

दूरभाष

निवास पता



ओम प्रकाश यादव

0172-2740867

2791823

68/7

राज्य मंत्री,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
स्वतंत्र प्रभार
(कमरा नं० 43-सी/8, सचिवालय)

चण्डीगढ़



कमलेश ढांडा

0172-2740358

2794617

73/7

राज्य मंत्री,
महिला एवं बाल विकास
स्वतंत्र प्रभार
(कमरा नं० 31/8, सचिवालय)

चण्डीगढ़



अनूप धानक

0172-2740195

2793155

76/7

राज्य मंत्री,
पुरातत्व एवं संग्रहालय
स्वतंत्र प्रभार
(कमरा नं० 47/8, सचिवालय)

चण्डीगढ़



संदीप सिंह

0172-2740892

2792072

72/7

राज्य मंत्री,
खेल एवं युवा मामले
स्वतंत्र प्रभार
(कमरा नं० 30/9, सचिवालय)

चण्डीगढ़

नई पहल



- वर्ष 2020 को 'सुशासन संकल्प वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय।
- वर्ष 2020-21 का बजट तैयार करने के लिए विभिन्न स्टेक होल्डर्स व विधायकों से विचार-विमर्श करने की पहल।
- प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में पांच करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाने का अधिकार।
- ग्राम सभा को शराब का ठेका न खोलने के लिए निर्णय की शक्ति, अब तक 872 प्रस्ताव प्राप्त।
- न्यायालयों के काम-काज में हिन्दी भाषा का उपयोग अनिवार्य करने का कानूनी प्रावधान।
- विश्व की 10 सबसे ऊँची चोटियों पर पहुंचने वाले हरियाणा के पर्वतारोहियों को 5 लाख रुपये नगद सहित ग्रेड 'सी' स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देने का निर्णय।
- कृषि आधारित उद्योगों को अभी तक बिजली के लिए इंडस्ट्रियल रेट लगाई जाती थी जिसे अब 4.75 रुपये प्रति यूनिट किया जा रहा है।
- उद्योगों में हरियाणा के अकुशल श्रमिकों को 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

नई योजनाएं

- 26 अक्टूबर, 2014 से अब तक 189 योजनाएं शुरू की गईं, जिनमें 53 केन्द्र व 136 राज्य की योजनाएं हैं, पिछले **100 दिनों में 4 केन्द्र व 6 राज्य की नई योजनाएं शुरू** की गईं।

	योजनाएं	विवरण
1	जल जीवन मिशन	वर्ष 2022 तक हर घर में नल से जल का लक्ष्य
2	अटल भू-जल योजना	भू-जल स्तर बढ़ाने के लिए 36 ब्लॉकों में शुरुआत
3	राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019	9वीं से 12वीं तक के बच्चों को भी मुफ्त पाठ्य पुस्तकें
4	पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना	पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर
5	लाल डोरा मुक्त गांव	गांव सिरसी से इस योजना की शुरुआत
6	अटल किसान मजदूर कैंटीन	किसान-मजदूर को 10 रुपये में खाना (27 दिसम्बर, 2019)
7	किलोमीटर स्कीम	66 नई बसें शुरू
8	'ई-रवाना स्कीम'	खनन क्षेत्र में लागू
9	नई एक्स ग्रेशिया पॉलिसी	52 साल की उम्र से पहले मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी
10	ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी	200 STPs से 700 क्यूसेक पानी दोबारा इस्तेमाल



- 'सरल' पोर्टल में 46 सेवाएं जोड़ी गईं, जिन्हें मिलाकर अब कुल 527 सेवाएं हो गईं।
- 'लोकायुक्त पोर्टल' का 25 दिसम्बर, 2019 को शुभारम्भ।
- सिरसी गांव (करनाल) को 'लाल डोरा मुक्त' करने के लिए 'डिजिटल मैप' का शुभारम्भ। राज्य में 15 जिलों के 75 गांवों की मैपिंग का कार्य शुरू।
- प्रदेश के पहले लाल डोरा मुक्त गांव सिरसी में 26 जनवरी, 2020 को ग्रामीणों को 'प्रोपर्टी की टाइटल डीड' का वितरण किया गया।
- लाल डोरा मुक्त होने से गांव की सम्पत्ति को विशेष पहचान मिलने के साथ-साथ भूमि मालिकों को मालिकाना हक मिला है, जमीन की खरीद-फरोख्त व उस पर ऋण लेने का अधिकार मिला है तथा इससे मालिकाना हक से सम्बन्धित विवादों पर भी अंकुश लगेगा।
- 'वेब-हेलरिस' का शुभारम्भ, प्रदेश की 91 तहसीलों/उप-तहसीलों में लागू।
- करनाल, पलवल, रेवाड़ी, पंचकूला, यमुनानगर, फरीदाबाद तथा गुरुग्राम में 'आधुनिक राजस्व रिकार्ड रूम' स्थापित व अन्य सभी जिलों में जल्द स्थापित होगा।
- रॉयल्टी एवं करों के संग्रहण को सरल बनाने और किसी भी प्रकार की कर चोरी को रोकने हेतु खनन के क्षेत्र में 'ई-रवाना' सिस्टम राज्य में एक जनवरी, 2020 से लागू।



कृषि



- 'मेरी फसल-मेरा ब्यौरा' पोर्टल के माध्यम से किसान द्वारा बोई गई फसल का ऑनलाइन ब्यौरा उपलब्ध, पोर्टल पर अब तक 5.61 लाख से अधिक किसान पंजीकृत।
- किसानों व मजदूरों को 10 रुपये प्रति थाली की दर से रियायती भोजन उपलब्ध करवाने के लिए करनाल में 'अटल किसान-मजदूर कैटीन' शुरू तथा जल्द ही पंचकूला, भिवानी, फतेहाबाद व नूंह में शुरू की जाएंगी।
- इस योजना के प्रथम चरण में 25 मण्डियों में यह सुविधा शुरू करने का निर्णय।
- अक्टूबर व दिसम्बर, 2019 में ओलावृष्टि से फसलों को हुये नुकसान का आंकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी के आदेश दिये।
- पराली न जलाने व पराली के उचित प्रबंधन के लिए धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल या 1000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 3538 किसानों को 1.62 करोड़ रुपये वितरित।
- सहकारी समितियों के किसानों के पुराने ऋणों की एकमुश्त निपटान स्कीम के तहत 3,33,420 किसानों का 620.90 करोड़ रुपये की ब्याज राशि माफ।
- अत्याधिक भू-जल दोहन व निरन्तर घटते भू-जल स्तर वाले राज्य के 36 ब्लॉकों में भू-जल स्तर में सुधार करने के लिए 'अटल भू-जल योजना' शुरू।
- इस योजना के तहत तीन वर्षों में कुल 712 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, जिसके प्रथम चरण में 150 करोड़ रुपये की राशि जारी।
- रबी सीजन 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर गेहूं 1925 रुपये, जौ 1525 रुपये, चना 4875 रुपये, मसूर 4800 रुपये, सरसों 4425 रुपये तथा सूरजमुखी 5650 रुपये प्रति क्विंटल किया गया।



बागवानी



- 'भावान्तर भरपाई योजना' में 5 नवम्बर, 2019 से गाजर, मटर, शिमला मिर्च, बैंगन, अमरूद व किन्नू भी शामिल, जिसके तहत गाजर का 700 रुपये, मटर व किन्नू का 1100 रुपये, शिमला मिर्च का 900 रुपये, बैंगन का 500 रुपये व अमरूद का 1300 रुपये प्रति क्विंटल **संरक्षित भाव निर्धारित**।
- **जल शक्ति अभियान** के अन्तर्गत व्यक्तिगत जल संग्रह नये तालाबों के निर्माण पर अनुदान सीमा 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक की गई।
- **सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा** देने हेतु अनुदान राशि बढ़ाकर 65 से 85 प्रतिशत की गई।



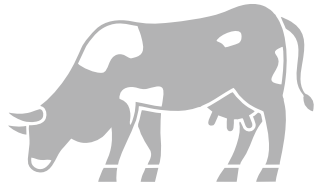
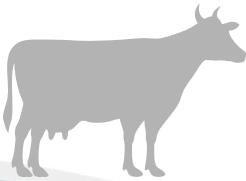
www.hortharyana.gov.in

दूरभाष - 0172-2582322

पशुधन



- 2.25 लाख पशुओं का बीमा करने वाला हरियाणा विश्व का एकमात्र राज्य ।
- एक लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण ।
- राजकीय पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों में पशुधन औषधि बैंक खोले गये ।
- छठी से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पशुओं के पालन-पोषण हेतु प्रेरित करने के लिए पशु ज्ञान गंगा विडियो का शुभारंभ ।



बिजली



- किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए 8 घंटे की जगह **10 घंटे बिजली की आपूर्ति** ।
- 'ट्यूबवेल बिजली बिल जुर्माना माफी योजना-2019' के तहत 71,322 किसानों के ट्यूबवेल के बिजली बिलों की **15 करोड़ 46 लाख रुपये की जुर्माना राशि माफ**, यह योजना 15 फरवरी, 2020 तक जारी रहेगी ।
- राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक-2019 में हरियाणा को देश में प्रथम स्थान प्राप्त । यह सूचकांक भवन, कृषि, डिस्कॉम, परिवहन, उद्योग एवं नगरपालिका क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखते हुये 97 महत्वपूर्ण मानकों को आधार मानकर तैयार किया जाता है ।



सामाजिक कल्याण

विभिन्न सामाजिक सम्मान भत्तों में बढ़ोतरी

भत्ता/पेंशन योजना का नाम	पात्र व्यक्ति	पहले	अब (जनवरी, 2020 से लागू)
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना	60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति	2000 रुपये	2250 रुपये
किन्नर भत्ता योजना	-----	2000 रुपये	2250 रुपये
विधवा एवं बेसहारा महिलाओं की पेंशन योजना	विधवा एवं बेसहारा महिलाएं	2000 रुपये	2250 रुपये
बौना भत्ता योजना	-----	2000 रुपये	2250 रुपये
दिव्यांग पेंशन योजना	18 वर्ष या अधिक आयु के 60 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति	2000 रुपये	2250 रुपये
लाडली पेंशन योजना	45 वर्ष या इससे अधिक 60 वर्ष की आयु तक के माता-पिता, जिनकी एक या एक से अधिक केवल लड़कियां हों और वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो	2000 रुपये	2250 रुपये
दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता	18 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले असमर्थ बच्चे	1400 रुपये	1650 रुपये

- निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना के अन्तर्गत बच्चे के माता-पिता/संरक्षक, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो, को बच्चे की 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक दी जाने वाली वित्तीय सहायता जनवरी, 2020 से **1100 रुपये से बढ़ाकर 1350 रुपये** मासिक की गई।
- 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' के अन्तर्गत 12 दिसम्बर, 2019 से सामूहिक विवाह करने वाले दूल्हा/दुल्हन में से यदि कोई एक हरियाणा निवासी है, तो उसे **51,000 रुपये** दिये जाने का प्रावधान।
- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मेडिकल के पी.जी. पाठ्यक्रमों में नियमित आरक्षण किया गया।

जन सुविधाएं



- 'परिवार पहचान-पत्र कार्यक्रम' के तहत सभी परिवारों को पहचान-पत्र बनवाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।
- 'मेरा परिवार-मेरी पहचान' पोर्टल शुरू, इससे वास्तविक लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा व डुप्लीकेसी की सम्भावनाएं कम होंगी।
- 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' के तहत निम्न आय वाले हर पात्र परिवार (जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख, दो हैक्टेयर भूमि जोत तक) को बीमा और पेंशन के प्रीमियम तथा नकद मिलाकर 6,000 रुपये वार्षिक आर्थिक सहायता का प्रावधान।
- अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नम्बर 1800-2000-023 जारी।
- इस योजना के तहत पंजीकरण का शुभारम्भ 26 जनवरी, 2020 से करनाल के सिरसी गांव से किया गया।



www.socialjusticehry.gov.in

दूरभाष - 0172-2713277

बालिका समृद्धि



- प्रदेश में लिंगानुपात की दर वर्ष 2019 में बढ़कर 923 हुई।
- प्रदेश में तेजाब पीड़ित महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता योजना के तहत घटना के समय से तीन वर्ष पहले हरियाणा में रहने की वर्ष 2011 में लागू की गई शर्त को हटाया।
- 6वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को हर महीने छः सैनेटरी पैड का एक पैकेट मुफ्त दिये जाने का निर्णय।
- छात्राओं को स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण देने का निर्णय।
- हरियाणा पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का निर्णय।



- एक लाख 80 हजार रुपये से कम आय व 5 एकड़ से कम भूमि जोत वाले परिवारों को 'आयुष्मान भारत योजना' के तहत निःशुल्क उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने का निर्णय।
- बहादुरगढ़ (झज्जर) व बावल (रेवाड़ी) में 100-100 बिस्तरों का ई.एस.आई. अस्पताल के लिए भवन का निर्माण करवाने का निर्णय।
- औद्योगिक क्षेत्र करनाल, तरावड़ी (करनाल), कैथल, कुरुक्षेत्र, नूंह, नारायणगढ़ (अम्बाला), औद्योगिक क्षेत्र रोहतक व चरखी दादरी में नई ई.एस.आई. डिस्पेंसरी खोलने का निर्णय।
- मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ई.डब्ल्यू.एस के प्रार्थियों को भी 10 प्रतिशत आरक्षण।



शिक्षा



- 'हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा' की मान्यता 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष की।
- 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019' के तहत हरियाणा में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रावधान।
- वंचित अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के बिल को स्वीकृति प्रदान।



कर्मचारी कल्याण



- आउटसोर्सिंग नीति के तहत कार्यरत महिला कर्मचारियों को 9 दिसम्बर, 2019 से नियमित महिला कर्मचारियों के समकक्ष मातृत्व अवकाश की सुविधा।
- 'क्लास वन' सरकारी अधिकारी से सीधा आई.ए.एस. बनने के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग को प्रदेश सरकार की ओर से भेजे जाने वाले नामों के लिए वर्ष 2020 से 'हरियाणा लोक सेवा आयोग' के माध्यम से अब लिखित परीक्षा का प्रावधान।
- एचटेट (H-TET) परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों के निवास स्थान से 50 किलोमीटर के दायरे में परीक्षा केन्द्र बनाए गये।
- 500 से अधिक कर्मचारियों वाले विभागों में ऑनलाइन स्थानान्तरण नीति मंजूर, 18 विभागों के 42 कॉडर के लिए यह नीति एक अप्रैल, 2020 से लागू होगी।
- पहली अगस्त, 2019 से लागू 'नई एक्स-ग्रेशिया स्कीम' के तहत सरकारी कर्मचारी के 52 साल की उम्र से पहले निधन होने पर आश्रित को अनुकम्पा आधार पर नौकरी मिलेगी।
- लापता सरकारी कर्मचारी के परिजन प्राथमिकी दर्ज होने के छः महीने बाद अनुकम्पा लाभ के हकदार होंगे।
- मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये की।
- मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार को मिलने वाला मकान किराया भत्ता या सरकारी आवास की अनुमति एक वर्ष की बजाय दो वर्ष की गई।

ग्रामीण एवं शहरी विकास



- गांव गुरावड़ा (रेवाड़ी) 'डिजिटल गांव' घोषित, अब एक क्लिक पर गांव के लोगों को सरकार की सैंकड़ों योजनाओं का लाभ।
- जो ग्राम सभा शराब का ठेका नहीं खोलने का प्रस्ताव पारित कर सरकार को देगी, उन गांवों में **शराब के ठेके न खोलने का निर्णय**, अब तक कुल 872 ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव प्राप्त हुये।
- भारत सरकार द्वारा 19 दिसम्बर, 2019 को जिला सोनीपत को **सराहनीय कार्य के लिए पुरस्कार** दिया गया।
- उन शहरी सम्पत्ति मालिकों को **सम्पत्ति कर में 10 प्रतिशत एकमुश्त छूट** प्रदान की गई, जिन्होंने वर्ष 2019-20 के अपने सभी देय कर/बकाया 31 जनवरी, 2020 तक चुका दिये।
- उन सम्पत्ति मालिकों को वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक के **संपत्ति कर के ब्याज में एकमुश्त छूट** दी गई, जिन्होंने सम्पत्ति कर के देय/बकाया 31 जनवरी, 2020 तक चुका दिये।

www.harpanchayats.gov.in
www.ulbharyana.gov.in

दूरभाष - 0172-2654725
दूरभाष - 0172-2570020

परिवहन



- राज्य परिवहन की बसों में 25 नवम्बर, 2019 से कैसर पीड़ित के एक सहयोगी को भी **मुफ्त यात्रा की सुविधा**।
- छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये '**छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना**' के तहत घर से दो किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों के लिए **छात्राओं को मुफ्त परिवहन सुविधा** दी जा रही है।



www.hartrans.gov.in

दूरभाष - 0172-2727263

कला व संस्कृति



- 'हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड' का गठन ।
- कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण मेले का आयोजन ।
- तीन दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव एवं शिल्प मेले का आयोजन ।
- गीता के उपदेशों के प्रचार-प्रसार के लिये गीता जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन ।



स्वच्छ पेयजल



- 'जल-जीवन मिशन' के तहत हर घर तक नल के द्वारा पीने का स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित।
- इस योजना के तहत 30 जून, 2020 तक 70 प्रतिशत, 30 जून, 2021 तक 80 प्रतिशत तथा 30 जून, 2022 तक 100 प्रतिशत घरों को नल से जल देने का लक्ष्य रखा गया है।



सुदृढ़ कानून व्यवस्था



- मधुवन स्थित पुलिस कॉम्प्लेक्स में फॉरेंसिक साइंस प्रयोगशाला (एफ.एस.एल.) के “ट्रैकिया” बार-कोडिंग सिस्टम का शुभारंभ ।
- अम्बाला रेंज में 5 नये पुलिस थाने खोलने की स्वीकृति ।
- प्रत्येक जिले में मॉडर्न पुलिस थाना बनाने का निर्णय ।
- अवैध खनन को रोकने के लिए विशेष अभियान में 760 से अधिक जेसीबी, ट्रक, डम्पर, ट्रैक्टर व ट्रॉली जब्त किये गए ।
- पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत 85 आरोपियों को अपराधी ठहराया गया ।



सेवा, सुरक्षा, सहयोग

www.haryanapoliceonline.gov.in

दूरभाष - 0172-2587900

महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट

- जींद में 664 करोड़ रुपये की लागत से **मेडिकल कॉलेज** बनाने की स्वीकृति।
- 282 करोड़ रुपये की लागत से 11 **ROB/RUB** और पुलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर।
- **सोनीपत-गोहाणा-जींद** रेलवे लाइन पर बड़वासिनी में 200 करोड़ रुपये की लागत से **ROB** की स्वीकृति।
- 37 करोड़ रुपये की लागत से **भिवानी व गुरुग्राम में सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर।**
- बहादुरगढ़ में 124 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से **बाईपास** स्वीकृत।
- बिजली के **10 सब-स्टेशन** स्थापित, **18 सब-स्टेशनों की क्षमता** बढ़ाई गई।
- 157 कि.मी. लम्बी **20 नई लाईनें** बिछाई गईं।
- होडल में **राजकीय महाविद्यालय** और पंचकूला में **संस्कृति मॉडल स्कूल** खोला गया।
- मनसा देवी, पंचकूला में संस्कृत महाविद्यालय खोलने की मंजूरी।
- अलेवा में 1.65 करोड़ रुपये की राशि से **बस अड्डा** निर्मित।
- पंचकूला में प्रदेश की पहली **संयुक्त फूड व ड्रग टेस्टिंग लैब** खोलने की मंजूरी।
- अम्बाला कैंट, रेवाड़ी व पानीपत के **अस्पताल अपग्रेड** करके 200 बिस्तर के बनाये गये।
- **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र** मूनक, जिला करनाल और दो उप-स्वास्थ्य केन्द्र-नारायणा, जिला करनाल और कोयल, जिला जींद खोले गए।
- **बहादुरगढ़ व बावल** में 100 बिस्तरों के **ई.एस.आई. अस्पताल भवनों** के निर्माण को स्वीकृति।
- औद्योगिक क्षेत्र **करनाल, तरावड़ी, कैथल, कुरुक्षेत्र, नूंह, नारायणगढ़** तथा औद्योगिक क्षेत्र **रोहतक व चरखी दादरी** में **ई.एस.आई. अस्पताल** खोलने का निर्णय।
- **सोनीपत के सेरसा** में 16 एकड़ भूमि में मसाला मंडी, **गुरुग्राम** में 8 एकड़ भूमि में फूल मण्डी तथा **कुरुक्षेत्र** के गांव तलहेड़ी में 6.65 करोड़ रुपये की राशि से आधुनिक पैक हाऊस बनाया गया।

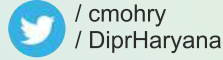
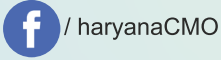
नई प्रशासनिक इकाइयां

26 अक्टूबर, 2014 से 26 अक्टूबर, 2019	100 दिन
• एक नया सैनिक कल्याण विभाग	• नागरिक संसाधन सूचना विभाग एवं विदेश सहयोग विभाग गठित
• सोनीपत नगर परिषद् को नगर निगम का दर्जा दिया	• नगर पालिका, झज्जर को नगर परिषद् बनाने का निर्णय
• सात नई नगर पालिकाएं बनाईं	• एक उपमण्डल—बादशाहपुर, जिला गुरुग्राम
• 12 नये उप-मण्डल बनाए गए	
• 11 नई तहसीलें व 10 नई उप-तहसीलें बनाईं गईं	
• चरखी दादरी को नया जिला बनाया गया	
• करनाल व फरीदाबाद दो नये मण्डल बनाए गए	

महत्वपूर्ण अवॉर्ड

हरियाणा को विभिन्न क्षेत्रों में 26 अक्टूबर, 2014 से अब तक कुल 122 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए, पिछले 100 दिनों में 8 पुरस्कार हुए प्राप्त।

राष्ट्रीय पुरस्कार	क्षेत्र
• गोल्ड अवार्ड	• अंत्योदय सरल परियोजना
• ऊर्जा दक्षता सूचकांक-2019 में प्रथम रैंक	• ऊर्जा दक्षता
• एक्सिलेंस इन कौस्ट मैनेजमेंट में प्रथम पुरस्कार	• बिजली लागत घटाने के लिए
• कृषि कर्मण पुरस्कार	• सरसों उत्पादन
• सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य पुरस्कार	• पशुपालन के क्षेत्र में
• स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2019 पुरस्कार में उत्तरी क्षेत्र में प्रथम	• स्वच्छता
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय पुरस्कार	• दिव्यांगजनों के लिए Best Accessible Website
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में तीसरा पुरस्कार	• गर्भवती/स्तनपान कराने वाली महिलाएं



महिला सुरक्षा हेल्पलाइन - 1091

चाइल्ड हेल्पलाइन - 1098



हरियाणा हेल्प डेस्क - 1800-180-2128

चौकसी हेल्पलाइन - 1064



चौकसी टोल फ्री - 1800-180-2022

निदेशक- सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग, हरियाणा द्वारा प्रकाशित
तथा संवाद सोसायटी के माध्यम से मुद्रित। (फरवरी, 2020)